वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्त-शिल्प, पटसन तथा कपास सहित वस्त्रों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार थी:–

	(मिलियन अमरीकी डालर)
1992–93	6599.62
1993–94	7973.91
1994–95 (फरवरी, 95 तक)	8999.23

(ग) गुजरात सहित भारत से वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार कई कदम उठा रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में निर्यातकों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना । निर्यात उत्पादन के लिये रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देना, निर्यात उत्पादन के लिये कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने के लिये विशेष व्यवस्था करना । निर्यात ऋण की बढी हुई उपलब्धता आदि सुनिश्चित करना, आदि ।

Increase in Market Development Assistance

4466. SHRI HIPHEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 332 given in Rajya Sabha on 14th March, 1995 and State:

(a) Whether the increase in Market Development Assistance will help the handloom Weavers and their societies in any way;

(b) If so, the details thereof;

(c) Whether Government propose to take some steps ensuring betterment of Weavers through this scheme; and

(d) If so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) With reference to amendment in the guidelines of Market Development Assistance Scheme (MDAS), the following assistance would be available to the Primary Societies:

(i) Primary Handloom Cooperative Societies would not be eligible for MDA at the rates which are higher than the previous rates.

(ii) All Primary Handloom Co-op. Societies irrespective of the fact whether these are availing cash credit or not would henceforth be eligible for MDA.

(iii) Withdrawal of erblock option earlier exercised by each State Govt. and Union Territory would now bring more and more Primary Handloom Cooperatives under the coverage of the scheme.

(iv) Even now Primary Handloom Cooperative Societies which have been formed after 1988-89 would be eligible for MDA if they fulfill the other eligibility conditions. In view of the modification in the guidelines of the scheme of MDA scheme in respect of Primary Handloom Weavers Coop. Societies the weavers would be benefitted in the following manner:

(a) The weavers will gradually like to come under the fold of cooperative societies since the Primary Handloom Cooperative Societies would now have wider coverage under the scheme.

(b) The Primary Handloom Coop. Societies would now diversify their sale of products.

(c) With the strengthening of financial health of the Primary Coop. Societies through the revised scheme, the weavers would benefit in terms of employment, sustained production and higher wages.

(d) The incident of accumulation of stocks which used to be reported in the past will gradually diminish.

Outstanding dues of Gujarat Government with NTC

4467. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the details of he outstanding dues from National Textile Corporation to the Gujarat Government as on December, 1994;

(b) the reasons for non-payment of the dues; and

(c) by when the dues are expected to be paid to the Gujarat Government?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) As on 31.12.94, NTC owes an amount of Rs. 18.89 crores covering cotton dues and dues pertaining to ESI, electricity, municipal taxes and other taxes.

(b) and (c) NTC has been facing an acute working capital shortage. NTC is expected to clear the outstanding dues depending upon the availability of working capital.

कपास उत्पादकों को उचित मूल्य

4468. **श्री संघ प्रिय गौतम :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात के कई कपास उत्पादक जिन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में वित्तीय संकट का सामना कर रहे कपास उत्पादकों के पक्ष में कोई पहल की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं। सभी किस्म की कपास की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक बनी रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को पर्याप्त लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित की जाती है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हस्तशिल्पों के विकास के लिये वित्तीय सहायता

4469. **श्री इकबाल सिंह :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पंजाब में आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अब तक हस्तशिल्पों के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर पंजाब में हस्तशिल्पों के विकास और उनको बढ़ावा देने के लिये कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ; और

(ग) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजाब के शिल्पकारों को कोई विशेष राहत प्रदान करने का विचार रखती है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (के) हस्तशिल्प राज्य का विषय है। तथापि, पंजाब राज्य सहित देश में हस्तशिल्प के